

3 कथित दुर्व्यवहार के विरोध में गोड समाज का प्रदर्शन

5 विधि और संसदीय लोकतंत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति

7 मानसून की विदाई, जलसंकट की दस्तक!

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 22

प्रति सोमवार, 19 अक्टूबर 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इशारे पर हो रही है केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपेक्षा?

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सब ठीक चल रहा है? क्या मध्यप्रदेश सरकार और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच तालमेल सही बैठ नहीं पा रहा है? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश की मोहन सरकार में उपेक्षा हो रही है वह संकेत ठीक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यह संकेत साफतौर पर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा में अंतर्कलह बुरी तरह से मची हुई है। वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में तालमेल जम नहीं पा रहा है जो अब पार्टी की बैठकों में, नेताओं के बयानबाजी में साफतौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मोहन

मोहनजी इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि लंबे समय बाद भी प्रदेश में मामा नहीं बन सके!



सरकार में वरिष्ठ मंत्रियों, नेताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आलाकमान भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर स्थितियाँ ऐसी ही रहें तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश भाजपा दो हिस्सों में बंट जाएगी और आगामी चुनाव का दृश्य कुछ और ही दिखाई देगा।

आखिर क्यों नाराज हुए शिवराज?

मध्यप्रदेश की राजनीति में सक्रिय रूप से 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ समय से मोहन सरकार की कार्यशैली से खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले विदिशा में एक रैली के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार के खिलाफ मुखर हो गये थे। इस बार तो हद ही हो गई और शिवराज सिंह चौहान को अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय जननेता हैं और जनता से जुड़ाव उनका साधारण नहीं है। (शेष पेज 2 पर)

बच्चों में गढ़ा जा रहा विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सेवा संकल्प से जनभागीदारी को मिल रही नई दिशा

-विजया पाठक

बच्चों का स्वस्थ बचपन, माताओं का बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण मुक्त समाज किसी भी विकसित राज्य की मजबूत नींव होते हैं। इसी सोच को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ में सुपोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सेवा, संवेदनशीलता और जनकल्याण की भावना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प राज्य में विकास की अवधारणा को नई



दिशा दे रहा है। इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा 'आंगन मिलन उत्सव' गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वस्थ भविष्य और पोषण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान की भावना जनभागीदारी और समाजसेवा के माध्यम से विभिन्न वर्गों तक पहुंच रही है। इस अभियान के मूल में सेवा को जनआंदोलन बनाने, समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने और जनकल्याणकारी प्रयासों को जनसहयोग से अधिक प्रभावी बनाने की सोच निहित है। (शेष पेज 2 पर)

युवा राजनीति के शोर में कमलनाथ के विजन की गुंज

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों युवाओं को लेकर गतिविधियाँ तेज हैं। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में सम्मेलन, संवाद कार्यक्रम और युवा कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके भविष्य, रोजगार, शिक्षा तथा प्रदेश के विकास को लेकर अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। राहुल गांधी के 'गुंज' कार्यक्रम से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के युवा संवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत की युवाओं से चर्चा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संवाद कार्यक्रमों तक, एक बात स्पष्ट है कि युवा अब प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हैं। लेकिन इस राजनीतिक सक्रियता के बीच एक सवाल भी उठता है कि



क्या युवाओं को लेकर राजनीतिक दलों की सोच केवल सम्मेलनों, भाषणों और संवाद कार्यक्रमों तक सीमित है या उसके पीछे रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का कोई ठोस विजन भी है? इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वर्ष 2018-19 के दृष्टिकोण और उनके

युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए बनाई थी दूरगामी योजनाएं

18 महीने के कार्यकाल का मूल्यांकन महत्वपूर्ण हो जाता है।

युवाओं को विकास का भागीदार मानने की सोच

कमलनाथ ने उद्योग, निवेश, व्यापार और आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर काम किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की चुनौती भी थी। उनके दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि प्रदेश की प्रगति को केवल सरकारी योजनाओं या बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विकास का वास्तविक लाभ तब दिखाई देता है, जब स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने, उद्यम शुरू करने और अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर मिलें। युवा आबादी किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। (शेष पेज 3 पर)

बच्चों में गढ़ा जा रहा विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य

(पेज 1 का शेष)

छत्तीसगढ़ में आंगन मिलन उत्सव इसी भावना को ग्रामीण जीवन से जोड़ने वाली पहल के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के विकास को केवल आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक प्रगति तक सीमित न रखकर सामाजिक सशक्तीकरण, महिला कल्याण, बच्चों के स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। स्वस्थ और सुपोषित बचपन की दिशा में किए जाने वाले प्रयास इसी व्यापक विकास दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्योंकि आज का स्वस्थ बच्चा ही कल के सक्षम, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ का आधार बनेगा।

सेवा संकल्प को जनभागीदारी से मिल रही मजबूती

आंगन मिलन उत्सव की विशेषता यह है कि यह पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषय को केवल सरकारी कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि इसे परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी बनाता है। गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम माताओं, बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों को एक मंच पर लाते हैं। जब किसी बच्चे के पोषण की चिंता केवल उसके परिवार तक सीमित न रहकर पूरे गांव की चिंता बनती है, तब सामाजिक सहभागिता का वास्तविक अर्थ सामने आता है। यही भावना सेवा संकल्प अभियान की मूल प्रेरणा से मेल खाती है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जनकल्याण की सोच को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता का महत्व विशेष रूप से रेखांकित होता है। आंगनबाड़ी केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र केवल बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और पोषण से जुड़े स्थान नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने, परिवारों में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

पोषण के साथ सम्मान और संवेदनशीलता का संदेश

आंगन मिलन उत्सव में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं का सम्मान तथा बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और दीदीयों का सम्मान सामाजिक सरोकारों को नई मजबूती देता है। महिलाओं का सम्मान केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उनके योगदान को



सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का अवसर है। परिवार और समुदाय के स्तर पर बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, खानपान और पोषण संबंधी जागरूकता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उनके योगदान को पहचानना समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। महतारी वंदन योजना जैसी महिला-केंद्रित पहल महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़ी व्यापक चर्चा का हिस्सा हैं। महिलाओं के सम्मान, उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता और परिवार के स्वास्थ्य में उनकी भूमिका को महत्व देने से कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक उद्देश्य अधिक व्यापक बनता है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों का सम्मान उन जमीनी कर्मियों के योगदान को रेखांकित करता है, जो समुदाय के बीच रहकर स्वास्थ्य, पोषण और जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और ज़रूरतमंद परिवारों को उचित मार्गदर्शन देने में इनकी भूमिका विशेष महत्व रखती है।

सुपोषण की रंगोली से स्थानीय खानपान का महत्व

आंगन मिलन उत्सव में अन्न के दानों से बनाई जाने वाली सुपोषण रंगोली पोषण के संदेश को सरल, सहज और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह रंगोली याद दिलाती है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारे घरों और खेतों में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सही उपयोग से होती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। परिवारों को खानपान की विविधता, भोजन की गुणवत्ता और बच्चों की उम्र के अनुसार आहार की ज़रूरतों के बारे में जागरूक

करना कुपोषण की रोकथाम में सहायक है। पोषण का संदेश जब स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से दिया जाता है, तो उसे समझना और दैनिक जीवन में अपनाना अधिक सहज हो जाता है। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। गीत, नृत्य और रचनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए सुपोषण का संदेश परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास बच्चों में जागरूकता के साथ समुदाय में सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

अन्न प्राशन और गोद भराई से मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर जोर

आंगन मिलन उत्सव में अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे कार्यक्रम मातृ-शिशु स्वास्थ्य के विभिन्न चरणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। अन्नप्राशन शिशु के जीवन में पूरक आहार की शुरुआत से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इसके माध्यम से परिवारों को बच्चे की उम्र के अनुरूप उपयुक्त आहार, भोजन की स्वच्छता और नियमित देखभाल के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सकता है। शिशु के शुरुआती वर्षों में उचित पोषण उसके शारीरिक विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए परिवारों को स्तनपान, समय पर पूरक आहार, भोजन की विविधता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सही जानकारी मिलना ज़रूरी है। किसी भी पोषण संबंधी समस्या की पहचान होने पर स्वास्थ्यकर्मियों से समय पर परामर्श लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहीं, गोद भराई कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और परिवार के सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल का सीधा संबंध मां

और बच्चे दोनों के कल्याण से होता है। ऐसे कार्यक्रम परिवारों को यह समझने का अवसर देते हैं कि मातृ स्वास्थ्य केवल महिला की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का साझा दायित्व है।

वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन

आंगन मिलन उत्सव में गांव के वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी विशेष महत्व रखती है। वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभवों के माध्यम से परिवारों को खानपान, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सामाजिक सहयोग के बारे में उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति स्थानीय ज़रूरतों को समझने और समुदाय को सामूहिक प्रयासों के लिए प्रेरित करने का अवसर देती है। पारंपरिक अनुभव और आधुनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का समन्वय पोषण जागरूकता को अधिक प्रभावी बना सकता है। हालांकि, बच्चों और गर्भवती महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य सलाह प्रमाणित चिकित्सकीय मार्गदर्शन और निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। इस तरह समुदाय की भागीदारी को सही जानकारी के साथ जोड़कर बेहतर परिणामों की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।

कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक संकल्प

कुपोषण केवल भोजन की कमी से जुड़ी समस्या नहीं है। इसके पीछे संतुलित आहार की अनुपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, स्वच्छता, जागरूकता और समय पर देखभाल जैसी अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए इसका प्रभावी समाधान भी बहुआयामी प्रयासों से ही संभव है। बच्चों के वजन और वृद्धि की निगरानी, गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, परिवारों को पोषण संबंधी जानकारी, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता की आदतें और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय से ज़रूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास की मजबूती तभी संभव है, जब विकास का लाभ गांवों, दूरस्थ क्षेत्रों और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सरकारी योजनाओं के साथ जनजागरूकता और सामाजिक सहभागिता की भूमिका भी अहम है।

क्या शिवराज का राजनीतिक करियर समाप्त करना चाहता है पार्टी हाईकमान?

(पेज 1 का शेष)

यही कारण है कि जब सीहोर जिले के आदिवासियों के कुछ गांवों को सरकार ने बेरहमी से तोड़ उन्हें बेघर कर दिया तो शिवराज सिंह चौहान को आदिवासियों का यह दर्द देखा नहीं गया और वे उन्हें सहायता देने सीहोर पहुंचे और अपनी ही सरकार को खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की हालत पस्त

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लगातार उपेक्षा होते देख मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हालत पस्त हो गई है।

यही कारण है कि इस बार जब शिवराज ने मंच से मोहन सरकार को चेतावनी दी तो वे सीधे मंत्रालय में पहुंचे और अफसरों के साथ बैठकर इस पूरे मामले की जांच कर मामले को शांत करने का आदेश दे दिया। सूत्रों के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मोहन यादव को पार्टी आलाकमान का निर्देश मिला है कि मप्र में शिवराज सिंह चौहान की उपेक्षा की जाये और उन्हें यहां ज्यादा सक्रिय न होना दिया जाये। निश्चित ही ऐसे माहौल में कहीं पार्टी आलाकमान को प्रदेश में तीसरे विकल्प पर विचार करना पड़े।

दोनों नेताओं में है वर्चस्व की लड़ाई

मंत्रालय सूत्रों और पार्टी सूत्रों के अनुसार दोनों ही नेताओं में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी कार्यालय से साफतौर पर आगामी चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान को किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में बैठाने की योजना चल रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते हैं कि वे मप्र की राजनीति से दूर हों इसलिए ही वह लगातार अलग-अलग

कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से मप्र में सक्रियता बनाये हुए हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान की यह सक्रियता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। दोनों ही नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनाव के पहले ऊंट किस करवट बैठता है।

क्या शिवराज हारिये पर जाने को तैयार नहीं हैं?

मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान के बीच चल रही खींचतान की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि

पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन शिवराज यह बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वे लगातार जल, जंगल, महिला और किसानों के विषयों पर सक्रियता के साथ लाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पहले शिवराज सिंह चौहान यादव के कंधे पर रखकर जो तीर चला रहा है क्या वह तीर शिवराज सिंह चौहान पर सही ढंग से लगाने में कामयाब होंगे या एक बार फिर चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान मुखर होकर पार्टी के विरुद्ध खड़े हो जायेंगे।

जनजातीय विद्यार्थियों से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में गोंड समाज महासभा का प्रदर्शन



-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, नरसिंहपुर। भोपाल में जनजातीय विद्यार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर नरसिंहपुर में गोंड समाज महासभा के युवा प्रकोष्ठ ने विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रेम सिंह दीवान को सौंपा गया। महासभा के अनुसार, 13 अक्टूबर को भोपाल में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन के दौरान जनजातीय विद्यार्थियों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया। आरोप है कि

विद्यार्थियों द्वारा 'जय जोहार' अभिवादन किए जाने पर पुलिसकर्मियों ने अनुचित प्रतिक्रिया दी। इसके बाद विद्यार्थियों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

गोंड समाज महासभा ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। संगठन ने मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। महासभा का कहना है कि किसी भी समुदाय के विद्यार्थियों के

साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे।

अधिकारियों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देने की मांग

संगठन ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को जनजातीय संस्कृति, परंपराओं तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उचित व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी बताई। महासभा ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि मामले में न्याय सुनिश्चित कराना है।

अवैध खाद भंडारण पर कार्रवाई, किराए का मकान सील 665 बोरी यूरिया समेत टीएसपी और एनपीके खाद मिली, किसानों की शिकायत पर संयुक्त टीम ने की जांच



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, देवरीकला। किसानों की शिकायत पर कृषि, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देवरी में खाद विक्रेता हर्षित जैन के प्रतिष्ठान सहित किराए के मकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खंडेराव वार्ड के सहजपुर रोड एवं देवगुवा रोड स्थित किराए के मकानों में स्वीकृत गोदाम के अलावा खाद का भंडारण पाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान मौके से 665 बोरी यूरिया, 7 बोरी टीएसपी और 8 बोरी एनपीके खाद मिलने की जानकारी सामने आई। प्रशासन द्वारा संबंधित परिसरों को सील कर दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। बताया गया कि किसानों ने खाद निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचे जाने की शिकायत की थी। जांच के दौरान

किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराया गया।

खाद दुकान में अनाज का व्यापार भी मिला

जांच के दौरान खाद विक्रेता की दुकान में खाद के साथ अनाज-गल्ला का व्यापार संचालित होना भी पाया गया। दुकान में खाद और अनाज की बोरीयाँ एक साथ रखे होने पर कृषि विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दुकानदार को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। एसएडीओ उपायुक्त प्रजापति ने बताया कि किसानों की शिकायत पर निरीक्षण किया गया था। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अवैध रूप से खाद भंडारित पाए गए किराए के मकानों को सील कर दिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कमलनाथ की दूरदर्शी सोच में था युवाओं के भविष्य का विजन

(पेज 1 का शेष)

लेकिन यदि शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकते रहें, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को काम न मिले और छोटे शहरों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर न मिलें, तो जनसांख्यिकीय लाभ चुनौती में बदल सकता है।

निवेश और उद्योग से रोजगार तक की कड़ी

कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने निवेश आकर्षित करने और उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाए। उनके कार्यकाल में आयोजित मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश निवेश सम्मेलन भी इसी प्रयास का हिस्सा था। ऐसे आयोजनों की वास्तविक सफलता का आकलन केवल निवेश प्रस्तावों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके धरातल पर उतरने, स्थापित होने वाली इकाइयों और उनसे पैदा होने वाले रोजगार के आधार पर किया जाना चाहिए। कमलनाथ के विजन में औद्योगिक विकास और निवेश को रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा गया। इस सोच के पीछे एक व्यवहारिक तर्क था। जब किसी प्रदेश में उद्योग स्थापित होते हैं तो केवल कारखानों में ही नौकरियां नहीं बनतीं। परिवहन, पैकेजिंग, रखरखाव, आपूर्ति, विपणन, तकनीकी सेवाओं और छोटे कारोबारों में भी अवसर पैदा होते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं।

रोजगार देने वाला बनने का अवसर

मध्यप्रदेश जैसे राज्य में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय उत्पादों के विपणन

में व्यापक संभावनाएं हैं। यदि युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और मार्गदर्शन मिले, तो वे न केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। कमलनाथ के युवा विजन अनुसार उन्होंने स्वरोजगार को आर्थिक आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा। इस दिशा में किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि नए उद्यमों की स्थापना, उनके टिकाऊ बने रहने और उनसे पैदा हुए रोजगार के अवसर होने चाहिए।

18 महीने का कार्यकाल और अधूरे अवसरों का सवाल

कमलनाथ ने दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। मार्च 2020 में उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस अवधि में किसी भी सरकार की सभी दीर्घकालिक योजनाओं के परिणाम सामने आना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है। कमलनाथ के कार्यकाल का आकलन करते समय घोषित नीतियों, शुरू की गई पहलों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर करना जरूरी है। कमलनाथ के समर्थकों का मानना है कि उनके पास औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि थी, जिसे लंबा कार्यकाल मिलने पर और आगे बढ़ाया जा सकता था।

आज की युवा राजनीति और कमलनाथ की विरासत

वर्तमान समय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े विषयों पर जोर दे रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा युवा संवाद

कार्यक्रम आयोजित करना यह बताता है कि युवाओं की आकांक्षाएं अब राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। इसके बावजूद कमलनाथ के कार्यकाल को इस व्यापक बहस में शामिल करना जरूरी है कि मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार आधारित विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। युवा राजनीति का अर्थ केवल युवाओं के साथ मंच साझा करना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक आर्थिक व्यवस्था तैयार करना है।

अवसरों की राजनीति जरूरी

आज मध्यप्रदेश की राजनीति में युवा केंद्र में हैं। यह सकारात्मक स्थिति है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों पर युवाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का दबाव बढ़ता है। कमलनाथ के युवा विजन पर चर्चा का सार भी इन्हीं सवालों में छिपा है। उनके समर्थकों के अनुसार, औद्योगिक निवेश, आर्थिक विकास और रोजगार को एक साथ देखने की उनकी सोच मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण थी। उनके 18 महीने के कार्यकाल को इस दृष्टिकोण की संभावनाओं और सीमाओं, दोनों के आधार पर समझा जाना चाहिए। अंततः युवाओं का भविष्य किसी एक सम्मेलन, भाषण या राजनीतिक दावे से तय नहीं होगा। इसका निर्धारण उन नीतियों से होगा, जो शिक्षा को रोजगार से, कौशल को अवसर से और उद्यमिता को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ें। कमलनाथ की राजनीतिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

सम्पादकीय

काँकरोच जनता पार्टी का आंदोलन युवाओं की आवाज़ या लोकतंत्र की नई परीक्षा?

दिल्ली की सड़कों पर उठती काँकरोच जनता पार्टी की आवाज़ भारतीय लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। असहमति को केवल राजनीतिक विरोध समझकर सीमित किया जा सकता है, या उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए? इस आंदोलन की विशेषता इसका नाम और इसकी उत्पत्ति है। सोशल मीडिया पर व्यंग्य के रूप में उभरे इस अभियान ने युवाओं की नाराजगी को सार्वजनिक आंदोलन का रूप दिया। इससे पहले इस समूह ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर प्रदर्शन किए थे। अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता इसके प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। यह परिवर्तन बताता है कि डिजिटल मंचों पर व्यक्त असंतोष वास्तविक राजनीतिक लामबंदी में बदल सकता है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है, उसका वास्तविक आधार प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सत्यापन योग्य होनी चाहिए। यदि बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठते हैं, तो उनका समाधान तथ्यों और स्पष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए।

आंदोलनकारियों ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, वे पुनः पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि विवाद का निष्पक्ष परीक्षण हो, हटाए गए नामों के कारण सार्वजनिक किए जाएँ और प्रभावित नागरिकों को प्रभावी शिकायत निवारण उपलब्ध कराया जाए। आरोप अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं होते, लेकिन गंभीर आरोपों का जवाब भी केवल खंडन से नहीं दिया जा सकता। काँकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को केवल एक अपरंपरागत नाम या

सोशल मीडिया की लोकप्रियता के आधार पर खारिज करना उचित नहीं होगा। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। जब पारंपरिक राजनीतिक मंच उनकी चिंताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, तब वैकल्पिक आंदोलन लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। हालाँकि, किसी आंदोलन की वास्तविक शक्ति उसके समर्थकों की संख्या या नारों की तीव्रता से नहीं, बल्कि उसके तथ्यों, उद्देश्यों और रचनात्मक परिणामों से निर्धारित होती है। उसे भावनात्मक लामबंदी के साथ ठोस समाधान भी प्रस्तुत करने होंगे।

दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए जाने की घटनाओं ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का प्रश्न भी उठाया है। प्रशासन का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन प्रतिबंध और हिरासत आवश्यक, आनुपातिक तथा कानूनसम्मत होने चाहिए। वहीं आंदोलनकारियों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कानून के पालन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति को कुचलना उचित नहीं, लेकिन असहमति के नाम पर अव्यवस्था फैलाना भी समाधान नहीं है। संवाद, न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जवाबदेही ही इस टकराव से निकलने का बेहतर रास्ता है। काँकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सरकार, निर्वाचन आयोग और विपक्ष—सभी के लिए एक संदेश है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य हैं। इस आंदोलन का मूल्यांकन उसके नाम, व्यंग्य या राजनीतिक समर्थन से नहीं, बल्कि उसके उठाए गए सवालों की गंभीरता और उनके प्रमाणों से होना चाहिए। यदि यह आंदोलन तथ्यों पर आधारित विमर्श और संस्थागत सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह युवाओं की भागीदारी को नई ऊर्जा दे सकता है। अंततः लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि सत्ता सवाल सुनने को तैयार हो और आंदोलन सवालों के उत्तर प्रमाणों के साथ मंजूर।

सियासी गहमागहमी

क्या मुख्यमंत्री के लिए चुनौती बन गये हैं शिवराज?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चल रही अंदरूनी उठापटक अब जनता के सामने आने लगी है। दरअसल पिछले दिनों जिस ढंग से नाराज होकर शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ गये और उन्होंने सीहोर के अदिवासियों के साथ हुए बुरे बर्ताव पर नाराजगी जताई उसके बाद भाजपा दो हिस्सों में बंटी नजर आई। एक खेमा ऐसा था जिसने पूरी तरह से दबे हुए अंदाज में शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया तो दूसरा खेमा तो पिछले कई समय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली से बेहद नाराज है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने इस पूरी अफरातफरी को बेहतर ढंग से सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाना अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खास बात यह है कि आगामी कुछ समय में ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों होना है ऐसे में यदि समय रहते दो वरिष्ठ नेताओं के बीच इस तरह के तनाव को यही नहीं रोका गया तो निश्चिततौर पर यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है।

सरकार जवाबदेही से पीछे न हटे

मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए सरकारी धन के उपयोग, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सितंबर 2026 में उज्जैन में RDSS योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगाने में लगभग 36 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता का आरोप भी सामने आया। इससे पहले सरकारी खरीद और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगना भी है। यदि सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि वह तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे। आखिर जनता के धन का उपयोग किस आधार पर हुआ, टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या थी—इन प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक होने चाहिए। हालाँकि, आरोप लगना और भ्रष्टाचार सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच, दस्तावेजी साक्ष्य और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। विपक्ष को भी अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए, जबकि सरकार को जांच की मांगों का उत्तर तथ्यों के आधार पर देना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ठोस कार्रवाई से प्रदर्शित करे। यदि अनियमितता प्रमाणित होती है, तो दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अंततः जनता को आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ईमानदार प्रशासन, सरकारी धन का उचित उपयोग और स्पष्ट जवाब चाहिए।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता दर्शनाक हदें पार कर रही है।

यह सब आवाजों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे।

-राहुल गांधी

काबोल नेता @RahulGandhi



प्रदेश में पहली से बारहवीं तक पिछले साल वर्ष 2025-26 में 14,231,833 का नामांकन हुआ था। इस वर्ष 2026-27 में 13 अक्टूबर की स्थिति में यह नामांकन 13,365,225 है। पिछले साल की तुलना में यह अंतर 866,608 यानी 6 फीसदी कम है।

-कमलनाथ

प्रदेश काबोल अरब

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी: विधि, राजनीति और संसदीय लोकतंत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, जिनकी पहचान केवल राजनीतिक दल की सीमाओं तक नहीं रहती, बल्कि वे अपनी विधिक विद्वता, संवैधानिक समझ, तार्किक अभिव्यक्ति और संसदीय भूमिका के कारण भी विशिष्ट स्थान बनाते हैं। डॉ. अभिषेक

मनु सिंघवी ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल सिंघवी ने न्यायपालिका तथा विधायिका, दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। उनके पिता डॉ. लक्ष्मीलाल सिंघवी देश के प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, विद्वान और राजनयिक थे। बौद्धिक एवं विधिक वातावरण वाले परिवार में पले-बढ़े सिंघवी की रुचि आरंभ से ही अध्ययन, तर्क-वितर्क और सार्वजनिक जीवन की ओर रही। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। इसके पश्चात उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा एम.ए. और पीएच.डी. की उपाधियाँ अर्जित कीं। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी एक अल्पकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें कानून, अर्थव्यवस्था, शासन और संवैधानिक व्यवस्था जैसे विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया।

अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने व्यावसायिक जीवन में वकालत को प्रमुख आधार बनाया। संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, कॉर्पोरेट कानून और वाणिज्यिक विवादों में उनकी विशेषज्ञता रही है। उनकी तार्किक क्षमता और कानूनी विषयों पर गहरी पकड़ ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अधिवक्ताओं में स्थान दिलाया। महज 34 वर्ष की आयु में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। इसके बाद 37 वर्ष की उम्र में वे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए। इन उपलब्धियों ने उनकी विधिक प्रतिभा और पेशेवर प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया तथा कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक विमर्श में योगदान दिया। सिंघवी का राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। वे लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते रहे। उनकी वक्तव्य कला, तथ्यों पर आधारित तर्क और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने की क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक बहसों में एक जाना-पहचाना चेहरा बनाया। अप्रैल 2006 में वे पहली बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 2024 में वे तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और अप्रैल 2026 में उन्होंने अपने पाँचवें कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में शपथ ली। इस प्रकार उनका संसदीय अनुभव लगभग दो दशकों तक विस्तृत रहा है।

राज्यसभा में सिंघवी की भूमिका कानून, न्याय, प्रशासन और सार्वजनिक नीति से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। वे कार्मिक, लोक शिक्षा, कानून एवं न्याय सहित विभिन्न संसदीय समितियों से जुड़े रहे हैं। उनकी विधिक विशेषज्ञता उन्हें विधेयकों, संवैधानिक प्रश्नों और शासन संबंधी विषयों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत कानून, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर पार्टी की गतिविधियों में उनका योगदान रहा है। राजनीतिक वक्तव्यों और न्यायालयीन बहसों के अतिरिक्त सिंघवी लेखन तथा सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से भी सक्रिय रहे हैं। उनके लेखों और टिप्पणियों में लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं, संवैधानिक संस्थाओं तथा समकालीन राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचार देखने को मिलते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे वक्ता के रूप में बनी है, जो जटिल कानूनी विषयों को तर्कपूर्ण और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषता विधिक ज्ञान और राजनीतिक अनुभव का समन्वय है। न्यायालय में कानून की व्याख्या करना और संसद में सार्वजनिक नीतियों पर विचार रखना- ये दोनों भूमिकाएँ उनके सार्वजनिक जीवन को विशिष्ट बनाती हैं।

श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 107वीं जयंती

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। VISM ग्रुप ऑफ स्टडीज के गुरुबख्श सिंह सभागार में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 107वीं जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन डॉ. सुनील सिंह राठौर, चेयरपर्सन सरोज राठौर, ग्रुप निदेशक डॉ. प्रज्ञा सिंह, सहित संस्थान के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने राजमाता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उनके प्रेरणादायी जीवन, राष्ट्र के प्रति समर्पण, सामाजिक योगदान एवं जनसेवा के कार्यों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील सिंह राठौर ने कहा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का जीवन केवल राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच भी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि राजमाता का मानना था कि शिक्षित महिला न केवल अपने



परिवार, बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक योग्य, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना भी होना चाहिए।

अचलेश्वर महादेव न्यास में वैश्य समाज का दबदबा, अध्यक्ष राजेश ऐरन, सचिव राजकुमार महेश्वरी विजयी



-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के 9 वर्षों के बाद हुए निर्वाचन में वैश्य समाज का दबदबा रहा, घोषित परिणामों में कार्यकारी न्यासी को छोड़कर शेष 7 प्रमुख पदों पर वैश्य समाज के प्रत्याशी विजयी हुए। न्यायालय के आदेश पर संपन्न कराये गये चुनाव में अध्यक्ष राजेश ऐरन, सचिव राजकुमार महेश्वरी और न्यासी महेश मुदगल जीत दर्ज की है।

डॉ. पुरेन्द्र भसीन ने दी छात्रा को नई रोशनी

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। रतन ज्योति नेत्रालय के चेयरमैन एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने यूपीएससी की छात्रा के ट्रोमेटिक कैटेरेक्ट का इलाज कर छात्रा की आंखों और सपनों को नई रोशनी दी है। डॉ. भसीन ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रही नेहा रूपचंदानी को गंभीर चोट के बाद आंखों में ट्रोमेटिक कैटेरेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से उनका विजन बहुत धुंधला हो गया था। यहां तक कि छात्रा किताबें और नोट्स भी नहीं पढ़ सकती थी। छात्रा की दाहिनी आंख में +25 डायोप्टर एवं बाई आंख में +30 डायोप्टर की पावर थी। मरीज को मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि जब मरीज हमारे



पास आई तो पूरी जांच की एवं स्थिति का सही आकलन कर मरीज एवं परिजनों को बताया कि केस चुनौतीपूर्ण है मगर सही गणना, तकनीक और अनुभव के साथ इसे सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। डॉ. भसीन ने छात्रा के उपचार में फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटेरेक्ट सर्जरी, एआई आधारित आईओएल पावर कैल्कुलेशन, माइक्रो इंसीजन फेको टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज्ड आईओएल

सिलेक्शन फॉर पोस्ट ट्रोमेटिक आई एवं इंडा ऑपरेटिव रियल टाइम डिस्सीजन मेकिंग तकनीक का उपयोग कर आंखों को नई रोशनी दी। इस मौके पर छात्रा ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अब मैं सिर्फ देख नहीं पा रही हूँ, बल्कि मैं फिर से सपना देख पा रही हूँ।

गौरव का अवसर है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का बस्तर आगमन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास के संबंध में हमने राष्ट्रपति महोदया को बस्तर आने का आमंत्रण दिया था। पूर्व में बस्तर के मांडी-चालुकी प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान भी उनसे बस्तर आने का आग्रह किया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था।

उनका 22 एवं 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है। 23 अक्टूबर को वे जगदलपुर जाएंगी और वहां मुरिया दरबार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति महोदया का बस्तर आगमन हम सभी के लिए प्रसन्नता और गौरव का अवसर है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सली हिंसा से प्रभावित एवं अन्य दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दंतेवाड़ा में आयोजित शिविर को संबोधित किया है। सरकार का प्रयास है कि नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता मिले और वे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता का विषय है। भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले इस मैच में महिला दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इससे प्रदेश की माताओं-बहनों और बेटियों को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के साथ उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा।

स्त्री-शक्ति के नौ रूप नवजीवन के प्रतीक हैं



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

शारदेय नवरात्रों में एक बार फिर हम स्त्री शक्ति के नौ रूपों की पूजा कर रहे हैं। नवरात्र में जो नव उपसर्ग हैं, वे नौ की संख्या के साथ-साथ नूतनता के भी प्रतीक हैं। इस अर्थ में वे परिवर्तन के सूचक हैं। ये रूप-शक्ति, स्त्रीत्व और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। इन स्वरूपों की पूजा करते हुए स्त्री रूपी इन देवियों के भव्य रूप हमारी चेतना में उपस्थित रहते हैं। इन्हें शक्ति रूप इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब सृष्टि के सृजन काल में देव पुरुष, दानवों से पराजित हुए, तो उन्हें राक्षसों पर विजय

के लिए दुर्गा से अनुनय करना पड़ा। एक अकेली दुर्गा ने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अनेक राक्षसों का नाश कर सृष्टि के सृजन को व्यवस्थित रूप देकर गति प्रदान की। प्रतीक रूप में ये रूप अंततः मनुष्य की ही विभिन्न मनोदशाओं के परिष्कार से जुड़े हैं। इन मनोदशाओं को राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं, जो मनुष्य की नकारात्मक विकृतियों के भी प्रतीक हैं। इन रूपों के महत्व को जानते हैं।

नवदुर्गाओं में शैल पुत्री प्रथम दुर्गा मानी जाती हैं। इनके हाथों में त्रिशूल और कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन वृषभ है। शैल पुत्री अपने पूर्वजन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थीं और इनका नाम सती रखा गया। पिता की इच्छा के विरुद्ध सती ने भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया। किंतु इसमें शिव व सती को आमंत्रित नहीं किया। इसे सती ने शिव का अपमान माना और बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने अपने पिता को शिव को आर्पित करने के लिए बाध्य किया। किंतु प्रजापति ने शिव का उपहास उड़ाया और उन्हें बुलाने से इनकार कर दिया। तब सती ने क्रोधित होकर यज्ञ-कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव को जब सती के प्राण त्यागने का समाचार मिला, तो उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करा दिया। बाद में शिव सती के जले शव को कंधे पर लेकर भटकते रहे। पुराणों में उल्लेखित है कि इस दौरान सती के अंग बारह स्थानों पर गिरे। उन्हें बारह ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। अगले जन्म में यही सती शैलराज हिमालय के घर में पैदा हुईं और शैलपुत्री कहलाई। उन्हें ही पार्वती कहा जाता है।

दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है, श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से हुआ था। पहले इनका नाम शुभ लक्ष्मी को देखते हुए पार्वती रखा गया। बाद में नाद मुनि ने हिमालय को बताया कि यही पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं। इस रहस्य को जानने के बाद पार्वती ने शिव को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। इसके लिए देवी ने कठिन तपस्या की। इससे उनका शरीर कृशकाया में बदल गया। तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा ने उनके समक्ष उपस्थित होकर मनचाहा वर मांगने की प्रार्थना की। पार्वती ने शिव को मांगा। ब्रह्मा ने पार्वती को अर्शोवाद तो दिया ही, उनकी काया को भी सुंदर रूप में बदल दिया। यहीं ब्रह्मा ने तप का आचरण करने के कारण ब्रह्मचारिणी का नाम दिया।

माता दुर्गा के नौ रूप - नवदुर्गा



नवरात्रों के तीसरे दिन दुर्गा के शरीर से नई शक्ति के रूप में चंद्रघंटा की वंदना की जाती है। सिंह पर सवार ये देवी निडरता के साथ सौम्यता के गुणों से भी भरपूर हैं। इनके आभामंडल से अदृश्य शक्ति का विकिरण होता रहता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण है। इनके दस हाथ हैं, जिनमें खड्ग, अस्त्र-शस्त्र, बाण आदि विभूषित हैं। देवासुर संग्राम में इनके घंटे की भयानक ध्वनि से सैकड़ों दैत्य मारे गए थे। इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देती है।

दुर्गा का चौथा स्वरूप कूर्मांडा देवी का है। इनका निवास सूर्यलोक में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान सदैव प्रकाशित रहती है। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों में इन्हीं देवी का आलोक प्रदीप्त है। जब ब्रह्माण्ड का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा था, तब इन देवी ने अपनी मंदमुस्कान द्वारा अंड अर्थात् ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति की। इसी कारण इन्हें कूर्मांडा कहा गया। सिंह पर सवार कूर्मांडा अष्ट भुजाधारी हैं। इनके हाथों में कमण्डल, धनुष-बाण, कमल-पुष्प, अमृत-कलश, चक्र गदा और सभी प्रकार की सिद्धियां व जपमाला सुशोभित हैं।

दुर्गा का पांचवां रूप स्कंद माता का है। इनके पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। सिंह पर सवार इन देवी की चार भुजाएँ हैं। इनके दो हाथों में कमल पुष्प है एक हाथ वरदान की मुद्रा में है और दूसरा हाथ पुत्र स्कंद को गोद में लिए है। इस कारण ये

पद्मासना देवी भी कहलाती हैं।

इनके बाद छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य नामक ऋषि की वंशावली में एक प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन हुए हैं। ये दुर्गा के भक्त थे। इस भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गा ने कात्यायन को कोई वर मांगने को कहा। तब महर्षि ने दुर्गा से अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। दुर्गा ने यही वरदान दे दिया। कुछ समय बाद जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम के असुर का अत्याचार बढ़ गया, तब दुर्गा के तेज से कात्यायन की पत्नी की कोख से देवी कात्यायनी ने जन्म लिया। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस तेज में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज का भी समावेश है। चार भुजाधारी कात्यायनी का वाहन सिंह है। इनकी चार भुजाओं को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना गया है।

दुर्गा के सातवें रूप को देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनकी काया अमावस्या की गहरी काली रात की तरह काली है। इनके मस्तक पर तीन नेत्र विद्यमान हैं, जो ब्रह्मांड के समान गोल तथा तीन लोकों के प्रतीक हैं। इनके केस घने एवं बिखरे हुए हैं। इनके गले में विद्युत ज्वाला सी प्रकाशित माला पड़ी हुई है। सांस लेते समय इनके नासिका छिद्रों से अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। इनकी सवारी गधा है और ये चार भुजाओं वाली हैं। इनके दो हाथों में तलवार और नुकीला अस्त्र है। जबकि एक हाथ वरदान की मुद्रा में और दूसरा अभय की मुद्रा में है। इन देवी को राक्षस और भूत-प्रेत का विनाश करने वाली देवी माना जाता है। दुर्गा पूजन के आठवें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। महागौरी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या की। इस समय उन्होंने धूप, आंभी, वर्षा और ठंड के थपेड़े सहे। इस कारण उनका शरीर कृशकाय और काला हो गया। अंत में जब भगवान शिव ने पार्वती रूपी इन महागौरी को पत्नी रूप में स्वीकार किया तब शिव ने अपनी जटाओं से निकलने वाली गंगा की जलधारा से पार्वती का शरीर धोया। इस पवित्र और शुद्ध गंगाजल से पार्वती का मैल धुल गया और उनका शरीर गौर वर्ण की तरह चमकने लगा। इसी कारण ये महागौरी के नाम से जानी जाने लगीं। इनका वाहन बैल है और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत एवं सौम्य है।

नवरात्रि के अंतिम यानी नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने की परंपरा है। ये सभी रिद्धि-सिद्धियों की स्वामिनी हैं। पुराण कथाओं के अनुसार जब दुर्गा के मन में सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने शिव को उत्पन्न किया। शिवजी ने उत्पन्न होने पर दुर्गा से सिद्धियों की मांग की। शिव को सिद्धियां प्रदान करने के लिए एक अंश से देवी सिद्धिदात्री का जन्म हुआ। जो सभी प्रकार की सिद्धियों की ज्ञाता थीं। बाद में सिद्धिदात्री ने शिव को 18 प्रकार की दुर्लभ, अमोघ और शक्तिशाली सिद्धियां दीं। इनसे ही शिव में अलौकिक शक्तियों का तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद शिव ने विष्णु की ओर विष्णु ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का, विष्णु को सृष्टि पालन का और शिव को सृष्टि के संहार का दायित्व सुपुर्द किया।

ब्रह्माजी को जब नर एवं नारी के अभाव में सृष्टि की रचना असंभव लगने लगी, तब उन्होंने माता सिद्धिदात्री का स्मरण किया। तब सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर सिद्धियों द्वारा शिव का आधा शरीर नारी का बना दिया। इस प्रकार शिव आधे नर और आधे नारी के रूप में अर्द्धनारीश्वर कहलाए। तब कहीं जाकर ब्रह्मा की सृष्टि सृजन संबंधी समस्या का समाधान हुआ। दुर्गा के इन स्त्री रूपों में नारी की इतनी महिमा होने के बावजूद हम हैं कि न केवल स्त्री के साथ दुराचार कर रहे हैं, बल्कि कोख में भी स्त्री-भूषण की हत्या करने का महापाप कर रहे हैं। सही मायने में नवरात्रि व्रत उपवास का संदेश स्त्री के संरक्षण से जुड़ा है।

मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 63 मेधावी छात्र-छात्राओं तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। समारोह में हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20

प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत एवं सुशीला मेहंदीरता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि

विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा, जो सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे।



मानसून की विदाई, जलसंकट की दस्तक!

आज की बात



प्रवीण कुलकर्णी

स्यत्र तत्र लेखक

देता है और फिर हमारी लापरवाही की कीमत वसूलता है।

इस वर्ष इंदौर में मानसून बारिश लगभग 590 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि सामान्य स्तर करीब 929 मिलीमीटर है। अर्थात् लगभग 37 प्रतिशत की कमी। एक अक्टूबर की रिपोर्ट में इसे पिछले 26 वर्षों का दूसरा सबसे सूखा मानसून बताया गया। यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि शहर के जल प्रबंधन के लिए गंभीर चेतावनी है।

आंकड़े वर्षा की अनिश्चितता दर्शाते हैं। इस समय अब हमें यह समझना होगा कि जल प्रबंधन केवल अच्छी बारिश की उम्मीद पर नहीं छोड़ा जा सकता।

अक्टूबर में टैंकर, तो मई-जून में क्या होगा?

चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मानसून समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और शहर के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए टैंकर चलाने पड़ रहे हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह की रिपोर्टों में प्रतिदिन लगभग 300 टैंकरों के संचालन का उल्लेख है।

तालाबों की स्थिति भी चेतावनी दे रही है। 9 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार छोटी बिलावली और लिलोदी तालाब सूख रहे हैं जबकि बड़ी बिलावली में 3.4 फीट की पूर्ण क्षमता के मुक़ाबले केवल 12.1 फीट जलस्तर दर्ज हुआ। यह तस्वीर बताती है कि जलसंकट की आशंका केवल कागज़ों तक सीमित नहीं है।

भूजल पर दबाव बढ़ेगा

कम बारिश का वास्तविक प्रभाव जनवरी-फरवरी से अधिक स्पष्ट



हो सकता है, जब भूजल पर दबाव बढ़ेगा। गर्मियों में मांग बढ़ने से परेशानी और गंभीर हो सकती है। विशेषकर उन बस्तियों, कॉलोनीयों और बहुमंजिला इमारतों में, जहां बोरवेल या निजी टैंकर प्रमुख सहाय हैं।

समस्या केवल बारिश की नहीं, हमारी आदतों की भी है

इंदौर की चुनौती के तीन प्रमुख पहलू हैं - कम वर्षा, बढ़ती शहरी जल मांग और भूजल पर निर्भरता। तेजी से फैलती कंक्रीट की सतहें बारिश के पानी को जमीन में समाने से रोकती हैं। पानी नालियों से बह जाता है, लेकिन धरती की प्यास अथुरी रह जाती है।

यह भी समझना होगा कि वर्षा की कुल मात्रा ही सब कुछ नहीं होती। बारिश कितने दिनों में हुई, कितनी तेज हुई और कितना पानी जमीन में समाया, यह भी महत्वपूर्ण है। तेज बारिश से सड़कें डूब सकती हैं, फिर भी भूजल पर्याप्त रिचार्ज न हो। यही शहरी जल प्रबंधन की विडंबना है।

नगर निगम ने संभावित संकट को देखते हुए जलापूर्ति की समीक्षा और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान शुरू की है। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर नई टंकियां तैयार कर लगभग तीन करोड़ लीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। जानकारी की मांगें तो केवल टैंकर बढ़ाना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। प्रशासन को अभी से वाईबैर जल उपलब्धता का आकलन, पाइपलाइन लीकेज

की मरम्मत, अवैध जल दोहन पर नियंत्रण और भूजल स्तर की नियमित निगरानी करनी होगी। जल वितरण में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि संकट के समय कमजोर बस्तियां सबसे अधिक प्रभावित न हों।

हर घर बन सकता है जल संरक्षण का केंद्र

समाधान की शुरुआत हमारे घरों से हो सकती है। नहाने में अनावश्यक शॉवर चलाने के बजाय बाल्टी का उपयोग, ब्रश और शेविंग के दौरान नल बंद रखना, गार्डियों और आंगन की सफाई में पाइप के बजाय बाल्टी अपनाना छोटी लेकिन असरदार आदतें हैं।

रसोई में सब्जियां धोने के बाद बचा उपयुक्त पानी पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आरओ से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का गैर-पेय उपयोग संभव है। घर की टंकियों में ऑटो-कट लगाना, टपकते नल ठीक करना और सोसायटियों में पानी की खपत का हिसाब रखना भी जरूरी है।

आज की बचत ही कल की सुरक्षा है

मान लीजिए, किसी परिवार ने प्रतिदिन केवल 50 लीटर पानी बचाया। तो एक महीने में 1,500 लीटर और वर्ष भर में 18,250 लीटर पानी बच सकता है। यदि इंदौर के एक लाख परिवार ऐसा करें, तो प्रतिवर्ष लगभग 182.5 करोड़ लीटर की संभावित बचत होगी। यह अनुमान है, लेकिन सामूहिक प्रयास की शक्ति स्पष्ट करता है।

इंदौर ने जनभागीदारी से स्वच्छता को जनआंदोलन बनाया है। अब समय जल संरक्षण को भी उसी संकल्प से अपनाने का है। हर कॉलोनी में जल समिति बने, हर बड़ी इमारत की रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जांच हो और हर परिवार अपनी पानी की खपत घटाने का लक्ष्य तय करे।

हमें यह भी समझना होगा कि नर्मदा से मिलने वाला पानी अमूल्य सहाय है, लेकिन असीमित संसाधन नहीं। दूर से पानी लाने में ऊर्जा, धन और संसाधन खर्च होते हैं। इसलिए स्थानीय जलस्रोतों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

पानी का संकट केवल नलों के सूखने से शुरू नहीं होता, वह हमारी संवेदनशीलता के सूखने से शुरू होता है। अभी अक्टूबर है। हमारे पास तैयारी का समय है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश नहीं। यदि आज हमने पानी बचाने की आदत नहीं अपनाई, तो आने वाली गर्मियों में हमारी सबसे बड़ी चिंता तापमान नहीं, प्यास हो सकती है।

इंदौर को अब स्वच्छता के साथ जल संरक्षण में भी मिसाल बनना होगा। क्योंकि अगली पीढ़ी को विरासत में केवल विकसित शहर ही नहीं, पर्याप्त पानी वाला शहर भी देना है।

आपदाएँ बदल रही हैं प्रकृति का संतुलन

पर्यावरण की फ़िक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद

आग तो कहीं बेमौसम बारिश और भूकंप। ये सब प्रकृति का चेतावनी संकेत है। प्रकृति निरंतर चलने वाले एक संतुलित तंत्र की तरह काम करती है। वर्षा, नदियाँ, वन, भूजल, मिट्टी और जीव-जंतु आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन बार-बार आने वाली आपदाएँ इस संतुलन को तोड़ रही हैं। बाढ़, सूखा, अति-वर्षा, लू, चक्रवात, भूस्खलन और जंगल की आग अब केवल संकट के क्षण नहीं हैं बल्कि ये प्रकृति के स्वरूप को ही बदल रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण लू, अनियमित मानसून, तीव्र वर्षा और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ी है। सबसे स्पष्ट प्रभाव जल-चक्र पर पड़ा है। कहीं दिनों की बारिश एक

ही दिन में हो जाती है, जिससे शहरों में जलभराव होता है और नदियाँ उफान पर आती हैं। वहीं कई क्षेत्रों में लंबा सूखा पड़ता है, जिससे भूजल गिरता है, कुएँ सूखते हैं और कृषि संकट में फँसती है। भारत में 1950 से प्रतिदिन 150 मिमी से अधिक वर्षा वाली घटनाओं की आवृत्ति लगभग 75 प्रतिशत बढ़ी है। यह अस्तुलन नदियों, तालाबों, आर्द्र भूमियों और वनस्पति के स्वाभाविक चक्र को बिगाड़ रहा है। वन और वन्यजीव भी इस परिवर्तन के सबसे बड़े पीड़ित हैं। सूखे और असामयिक गर्मी से जंगलों में आग लगने की घटनाएँ बढ़ती हैं। भूस्खलन और बाढ़ से मिट्टी बह जाती है, पेड़ गिरते हैं और जीवों के आवास नष्ट होते हैं। हिमालय में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर झील फटने का खतरा बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल मानव बस्तियाँ प्रभावित होती हैं, बल्कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो जाता है।

समुद्री तटों पर बढ़ता समुद्री जलस्तर और तीव्र चक्रवात तटीय भूमि को क्षति कर रहे हैं। खारे पानी का भूजल में प्रवेश कृषि और पीने के पानी को प्रभावित करता है। तटीय आर्द्रभूमियाँ, मैंग्रोव और मछली पालन क्षेत्र खतरे में हैं। ये क्षेत्र प्रकृति के सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, इसलिए उनका हास आगामी आपदाओं को और भी विनाशकारी बना देता है। यह सच है कि आपदाएँ प्रकृति का हिस्सा रही हैं, पर अब उनकी आवृत्ति और तीव्रता असामान्य रूप से बढ़ी है। भारत में 1970 से अब तक 500 से अधिक चरम मौसमी घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश 2005 के बाद हुईं। इसका कारण केवल प्राकृतिक चक्र नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, आर्द्रभूमियों का नष्ट होना और

नदी-तटों पर अतिक्रमण भी है। यदि हमने अभी भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रकृति को बचाना, स्वयं को बचाना है। अब आवश्यकता केवल राहत और बचाव की नहीं, बल्कि जोखिम को पहले से कम करने की है। अंत में इसके उपाय भी बताना आवश्यक क्योंकि सिर्फ समस्या से अवगत कराना ही काफी नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए वृक्षारोपण, नदी-तटों की सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर जंगल खत्म और पहाड़ों को काटना, बांधों पर बाढ़, भूस्खलन व सूखा संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्र बनाकर वहाँ निर्माण पर नियंत्रण होना चाहिए। मजबूत भवन संहिता, चेतावनी प्रणाली, नियमित अभ्यास एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियाँ आवश्यक हैं। जनता को आपदाकालीन नंबर, सुरक्षित स्थान और बचाव विधियों की जानकारी देना अति आवश्यक है। योजनाकारों को भी ध्यान में रखना होगा। उपग्रह तस्वीरों, स्वचालित मौसम केंद्रों, भूकंपीय सेंसरों, ग्लेशियर निगरानी प्रणालियों, नदी के जलस्तर मापने वाले गेज और अस्थिर ढलानों को वास्तविक समय में निगरानी को एक साझा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना होगा।

नागरिकों को भी आपदा के समय शांत रहकर सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। जल, भोजन, दवाइयों और प्राथमिक चिकित्सा की पूर्व-तैयारी भी आवश्यक है। प्रकृति का तंत्र अपने आप ठीक हो सकता है, परंतु उसके लिए मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।



आस्था का दिव्य महाकुंभ पूरा विश्व देखेगा उज्जैन का वैभव



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

30 करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत

उज्जैन नगरी का हो रहा अभूतपूर्व कायाकल्प

सुगम आवागमन ₹ 13,536 करोड़ से

581 कि.मी. मार्गों का चौड़ीकरण
एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत

पुल निर्माण ₹ 440 करोड़ के

निर्माण से यातायात का
बेहतर प्रबंधन

शुद्ध जल क्षिप्रा के लिये ₹ 919 करोड़
लागत की कान्ह क्लोज्ड डक्ट परियोजना
एवं शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु
₹ 1113 करोड़ के कार्य जारी

घाट निर्माण लगभग 29 कि.मी.
घाटों का निर्माण जारी

जीरो वेस्ट इवेंट जन भागीदारी से
जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की पहल

मंदिरों का जीर्णोद्धार

सभी पौराणिक मंदिर जैसे हरसिद्धि,
गढ़कालिका का विकास

आधुनिक तकनीक से प्रबंधन

भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रांसपोर्ट और
कंट्रोल रूम तक एआई का उपयोग

कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय उज्जैन हवाई अड्डा और
सदावतल में 4 हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी

उज्जैन बनेगा मेडिकल हब

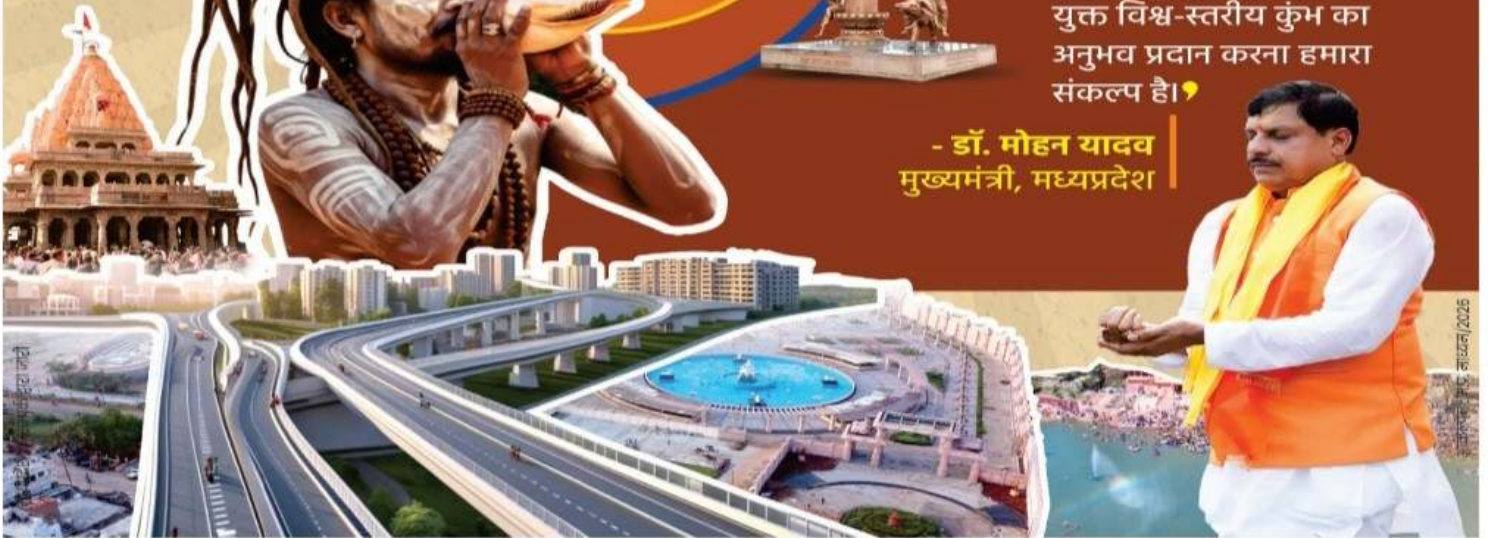
₹ 592.30 करोड़ लागत से मेडिसिटी एवं
मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन

सिंहस्थ 20 28

सिंहस्थ महापर्व 2028
करोड़ों भक्तों को सरल, सुलभ
और नवीनतम सुविधाओं से
युक्त विश्व-स्तरीय कुंभ का
अनुभव प्रदान करना हमारा
संकल्प है।

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

R.O. No. : D19225/26



स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)